एक विशेष जलवायु बैठक

लेखक- अभिताभ सिन्हा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

20 सितम्बर, 2019

"बेहतर और जरूरी समाधानों की पहचान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी सोमवार के हाई-प्रोफाइल विशेष शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, लेकिन भारत ने कहा है कि वह पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है।"

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए और इस संदर्भ में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए विश्व को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोमवार को एक विशेष जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने दुनिया के नेताओं से कहा है कि वे पहले से ही चल रहे कार्यों को बढ़ाने के लिए 'ठोस' और 'यथार्थवादी' प्रस्तावों के साथ सामने आएं।

हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महासचिव की बैठक में भाग लेने वाले कई नेताओं में से एक होंगे, लेकिन भारत पहले ही कह चुका है कि वह अपनी जलवायु कार्य योजना को उन्नत करने की स्थिति में नहीं है। इसके बजाय, इसने विकसित दुनिया को याद दिलाया है कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए विकासशील देशों को धन और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा करने पर अधिक ध्यान दें।

विशेष शिखर सम्मेलन क्यों?

यह पहली बार नहीं है कि जलवायु परिवर्तन पर एक विशेष बैठक महासभा सत्र के मौके पर हो रही है। इसी तरह की एक बैठक पिछले साल हुई थी। लेकिन इस वर्ष, बैठक में एक बड़ा प्रोफाइल है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष या सरकार शामिल हो सकते हैं।

लेकिन जो बात इस बैठक को पहले के प्रयासों से अलग बनाती है, वह महासचिव की मंशा है जहाँ वे इस सम्मलेन को विफल नहीं होने देना चाहते है। बैठक के लिए आमंत्रित करने वाले पत्र में, गुटेरेस ने दुनिया के नेताओं को बताया की इस बार वे सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि एक ठोस योजना के साथ आए। विशेष रूप से, उन्होंने देशों को 2030 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी लाने और 2050 तक 'शुद्ध शून्य' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी कार्य योजना बताने का आग्रह किया है। इसके अलावा, उन्होंने नौ क्षेत्रों की भी पहचान की है, जिनमें वह चाहते है कि देश और अधिक कार्य करें।

किस जलवायु कार्य योजना के बारे में बात हो रही हैं?

2015 के पेरिस समझौते के तहत, प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निर्धारित समय-सीमा वाले कार्यों को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करना है। 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDCs नामक कार्य योजनाओं का पहला सेट प्रस्तुत किया गया था। पेरिस समझौता यह भी कहता है कि NDC को हर पांच साल में अपडेट किया जाना चाहिए और प्रत्येक के बाद NDC मजबूत और पिछले की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए।

पांच साल के चक्र के अनुसार, देशों को अगले साल तक अपना दूसरा एनडीसी (NDC) जमा करना होगा। लेकिन महासचिव सोमवार की बैठक में देशों को विशिष्ट अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं बनाने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने देशों से 2020 के

बाद किसी भी नए कोयला संयंत्र की स्थापना नहीं करने, जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी बंद करने और प्रदूषकों पर अतिरिक्त कर लगाने का वादा करने की भी अपील की है। महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने सभी देशों को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए कहा है।

भारत ने क्यों किया इंकार?

भारत ने कहा है कि उसकी एनडीसी पहले से ही अपनी विकास अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए अपने 'सबसे अच्छे प्रयास' का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस सप्ताह के शुरू में जारी एक चर्चा पत्र में, सरकार ने कहा कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन के संदर्भ में महासचिव द्वारा कही गयी बात संपूर्ण अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव की ओर इशारा करती है, यह लक्ष्य केवल विकसित देशों के लिए ही रखा जाना चाहिए।

यह एक वैश्विक आकांक्षात्मक लक्ष्य हो सकता है और विकसित देशों को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए उपाय करने और कानून बनाने के लिए ट्रैक पर होना चाहिए। लेकिन यह विकासशील देशों के लिए एक लक्ष्य नहीं हो सकता है क्योंकि विकासशील देशों के पास उतनी तकनीकें नहीं हैं और न ही सभी उपलब्ध हैं। वित्त और प्रौद्योगिकी दोनों मोर्चे पर पिछले प्रदर्शन के संदर्भ में हालत उतनी अच्छी नहीं हैं।

चर्चा पत्र में, भारत ने विकासशील देशों को विकसित दुनिया द्वारा पर्याप्त वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने में उनकी विफलता पर भी ध्यान आकर्षित किया है। इसमें बताया गया है कि 2015 में उनके NDCs में विकासशील देशों द्वारा निर्दिष्ट वित्त की आवश्यकता 4.4 ट्रिलियन डॉलर तक है। अकेले भारत को कृषि, वानिकी, जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे में केवल अनुकूलन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 2030 तक 206 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। एनडीसी में सभी प्रस्तावित कार्यों को पूरा करने की कुल लागत 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर होगी।

विकसित देशों ने जो उपलब्ध कराया है वह उपलब्ध आंकड़ों की तुलना में अल्प है। विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए 2020 से हर साल कम से कम 100 बिलियन डॉलर जुटाने का वादा किया है। लेकिन इस मोर्चे पर भी, वे अब तक लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं।

भारत ने कहा, 'जलवायु निधि अद्यतन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विकसित देशों से जलवायु वित्त के लिए वास्तविक प्रतिज्ञा केवल 30 बिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि जमा और अनुमोदन क्रमशः 26 बिलियन और 19 बिलियन डॉलर है।'

इसने कहा है कि इस स्तर पर जलवायु क्रियाओं के लिए कोई भी आह्वान किया जाना चाहिए। 'जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक जलवायु वित्त पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।'

भारत ने कहा है कि जब तक वह जलवायु क्रियाओं पर 'अपना सर्वश्रेष्ठ' करना जारी रखेगा, वह इस चरण में 2050 के लिए शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य जैसे किसी दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा। पेरिस समझौते के तहत, देशों को 2023 में अपने कार्यों का लेखा-जोखा देना है, यह देखने के लिए कि क्या ये पूर्व-औद्योगिक समय से तापमान में वैश्विक वृद्धि को 2° C से नीचे रखने के उद्देश्य के अनुरूप थे।

तो, सोमवार की बैठक से क्या निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है?

सोमवार की बैठक से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 112 देशों ने अपनी एनडीसी को संशोधित करने का इरादा व्यक्त किया था, जिनमें से 75 ने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का भी वादा किया था। अन्य 37 ने अपने एनडीसी में अधिक डेटा और जानकारी लाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, कम से कम 53 देशों ने कहा था कि वे दीर्घकालिक रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे 2050 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करना। वैश्विक उत्सर्जन के 26 प्रतिशत के लिए केवल 14 देशों ने मिलकर, स्पष्ट रूप से कहा था कि वे अपने एनडीसी को संशोधित नहीं करेंगे। ये घोषणाएं कई देशों ने सोमवार की बैठक में की हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly)

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि जब दुनियाभर के नेता संयुक्त राष्ट्र के न्यूयार्क स्थित मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान सार्वजनिक विषयों पर चर्चा करेंगे तब जलवायु परिवर्तन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, 'हम प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के लिए खतरा बने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विशेष ध्यान देंगे।'
- गुटेरस 23 सितंबर को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जलवायु की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए 2019 क्लाइमेट एक्शन समिट की मेजबानी करेंगे।
- देशों और सरकारों के प्रमुख, सदस्य देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि और टीन एज कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के संयुक्त राष्ट्र द्वारा मौजूदा समय के निर्णायक बताए जा रहे मुद्दे से निपटने के उपायों पर विचार करेंगे।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में भाग लेंगे।

क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के तहत 1945 में इसकी जनरल असेम्बली यानी महासभा स्थापित की गई।
- यह महासभा संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श और नीति निर्माण जैसे मुद्दों पर प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करती है।
- 192 सदस्यों से बनी यह संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने चार्टर के तहत कवर किये गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुआयामी और बहुपक्षीय चर्चा के लिये एक बेहतरीन मंच प्रदान करती है।

अध्यक्ष का चुनाव

- महासभा के प्रत्येक अधिवेशन के तीन महीने पहले सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। वर्ष 2003 तक अध्यक्ष अधिवेशन के पहले सम्मेलन में ही चुन लिया जाता था।
- आरंभिक दो सप्ताहों के लिए, सामान्य विवाद जारी रहते हैं, जिसमें महासचिव और अध्यक्ष के बाद हर प्रतिनिधि को सभा के सामने व्याख्यान देने का अवसर प्रदान किया जाता है।

महासभा के कार्य

- 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' के स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार प्रयोग से उत्पन्न राष्ट्रसंघ की अकर्मण्यता के निवारण के लिए महासभा ने 1940 में 'लघुसभा' नामक एक अंतरिम समिति की स्थापना की थी।
- महासभा के सत्रावसान में महासभा का कार्य लघुसभा कर सकती है और महासभा का अधिवेशन बुला सकती है। इसके अनुसार, सुरक्षा परिषद में शांति एवं सुरक्षा के प्रश्नों पर एकसमान मत न होने पर, 24 घंटे की सूचना पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जो सामूहिक उपायों का प्रस्ताव और सैनिक कार्यवाही का निर्देश कर सकता है।
- 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' ने पिछले वर्षों में विश्व की विभिन्न जटिल समस्याओं पर विचार किया और कोरिया, ग्रीस, पैलेस्टाइन, स्पेन आदि के प्रश्न पर उचित कार्यवाही की।
- 1959 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल द्वारा स्वेज पर किए गए आक्रमण को रोकने में महासभा सफल हुई।

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर यूएन की इस अहम बैठक में बोलेंगे। इसके अलावा वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे।
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी।
- इस दौरान उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की अहम बैठक होने जा रही है।
- संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के दो भाषण होंगे, जिनका पूरी दुनिया को इंतजार है। भारत ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो काम किया है, उसकी पूरी दुनिया में धूम है। BS6 में परिवर्तन करने का हो, वनक्षेत्र बढ़ने का हो।
- पेरिस समझौते के पालन पर आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारे नए प्रयोग भी किए हैं। जैसे ई-मोबिलिटी को बढ़ाने पर फोकस किया है। तो ये सारी बातें वहां आएंगी। बाकी और फोरम भी वहां होंगे। उसमें हम भाग लेंगे।
- इस सम्मेलन में देशों की सरकारों, निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी, स्थानीय प्रशासनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और छह क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी समाधान तलाश करने के प्रयास किए जाएंगे:-
- वैश्विक स्तर पर नवीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ना
- टिकाऊ व मजबूत बुनियादी ढाँचे व नगर
- टिकाऊ कृषि
- वनों व समुद्रों का प्रबंधन
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए मजबूती और लचीलापन
- नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के साथ सार्वजनिक और निजी वित्तीय संसाधनों का आवंटन

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **हाल ही में एक विशेष जलवायु बैठक सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 45% की कमी लाने का विचार रखा गया।
   2. इसमें शुद्ध शून्य को प्राप्त करने का लक्ष्य 2050 तक रखा गया।
   3. भारत सरकार ने कहा कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य केवल विकसित देशों के लिए रखा जाना चाहिए।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3

   (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Recently a special climate meeting conference was organized by the United Nations. Consider the statements related to this-**

   1. In this conference, the idea was put by the UN Secretary-General to reduce the global greenhouse gas emissions by 45% by 2030.
   2. It has the target to achieve net zero by 2050.
   3. Government of India stated that net zero emission targets should be set for developed countries only.

   Which of the above statements are correct?

   (a) 1 and 2 (b) 2 and 3

   (c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: यूएन के तत्वाधान में प्रस्तावित विशेष पर्यावरणीय बैठक के महत्त्व को रेखांकित कीजिए। भारत के अभीष्ट निर्धारित लक्ष्य (INDC) की प्रगति का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)

Q. Underline the importance of a special environmental meeting proposed under the auspices of the UN. Present an analysis of the attainment of India's Intended Nationally Determined Contribution (INDC). (250 Words)

नोट : 19 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।